

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 22-जनवरी, 2008

विषय:-मै0 विश्वकर्मा आटोमोटिव प्रा0लि0 को जिला उधमसिंहनगर की तहसील किच्छा के ग्राम किशनपुर को औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल 0.413 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-291/सात-स0भू0अ0/2007 दिनांक 11 जनवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 विश्वकर्मा आटोमोटिव प्रा0लि0 को उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील किच्छा के ग्राम किशनपुर के खाता सं0 101 खसरा सं0 546, रकबा 0.413 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.....(2)

R

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं गवर्न उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) 2005 के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में प्रस्तावित होने वाले औद्योगिक इकाईयों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र इकाई के द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ओटोमोटिव से सम्बन्धित क्रियाकलापों की सीपना हेतु ही किया जायेगा।

.....(3)

12- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास का दायित्व सम्बन्धित इकाई को होगा और यह अनापत्ति/ सहमति पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं के लिये आधार के रूप में उद्धृत नहीं की जा सकेगी।

14- प्रश्नगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/ छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुरंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूवैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 8- श्री प्रवीन कुमार झाम्व, कालरा कालोनी पलवल, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, रुचिवालय।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडानी)
अनुसचिव।